shall apply to the settlement of all existing and future credit agreements and commercial transactions designated in Roubles between the USSR and the Republic of India."

It says "all existing and future credit agreements". This is, however, subject to this:

"Repayments made in respect of past and existing credits upto the date of signing of the Protocol at the old rate of exchange would be considered as final. However, in respect of credit agreements concluded on or after January 1, 1976, which contain a specific clause stating that a new rate of exchange that may be subsequently agreed upon between the two Governments shall apply, the new rate of exchange now agreed upon shall be applicable retrospectively from the date of conclusion of such agreements".

After 1976, in all our agreements this clause had been put in. When my hon. friend says that we are departing from the previous Government's policy, he should note the previous Government had realised that some readjustments were going to be necessary. And so they agreed upon this proviso being made in respect of those agreements.

DR. BHAI MAHAVIR: Are there any repayments which have fallen due but which have not been made?

SHRI H. M. PATEL: Whatever repayments were due have always been made on the relevant dates and they will be covered by this Protocol. There will be no additional liability in regard to those repayments that have been already made.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: What about retrospective liabilities?

SHRI H. M. PATEL: These arise in respect of existing agreements which provide for retrospective application of the new agreed rate of exchange. They will be worked out according to such agreements. With regard to the additional . . . (*Interruptions*) . . . Will you not disturb me till I have finished my reply? This is a difficult subject which please try to understand as I am also trying to explain it as clearly as possible. Additional liability means whatever additional amount we have to pay in respect of existing agreements against which we have not completed payments. That additional liability will be repayable in 45 years' interest-free loans. This is the arrangements that has been made and that reduces the burden on us. I have answered Mr. Kulkarni's point and also clarified it.

DR. BHAI MAHAVIR: Yesterday there was some retrospective part.

SHRI H. M. PATEL: Retrospective part is what I mentioned. All contracts entered after January 1, 1976 contain the clause that payments will be made in terms of whatever new agreements are entered into. Therefore, it is in regard to that that there will be retrospective effect.

श्री उपसभापति : अब सदन की कार्रवाई ढ़ ई बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at twenty seven minutes past one of the clock.

——

The House reassembled after lunch at thirty-six minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in teh Chair.

THE CONSTITUTION (AUTHORISED TRANSLATIONS) BILL, 1978—

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : डिपुटी चेयरमैन साहब, मै इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि यह तारीखी बात है कि हमारे दस्तूर, हमारी अपनी कौमी जुबान और दूसरी जुबानों में

[श्री खुरशीद आलम खान]

जो 8वें शड्यूल के अन्दर है तरजुमा किया जा रहा है । मैं इसकी भी अच्छी तरह से ताईद करता हूं कि यह काम इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आखिर अब जब यह काम शुरू किया जा रहा है तो यह एक अच्छा काम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के कामों में आइन्दा देरी नहीं होगी । मैं तो साफ तरीके से यह भी बता देना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दी का सवाल है हिन्दी हमारी कौमी जुबान बन चुकी है, यह राज सिहासन पर बैठ चुकी है, उसका अपना जो मुकाम है उसको मद्दनजर रखते हुए हमारी जो दूसरी रीजनल जुबानें हैं और दूसरी जो जुबानें जो 8वें शड्यूल के अन्दर है उनका और इस जुबान का मुकाबला करना बिल्कुल बेकार है । इसका मुकाम बहुत ऊंचा मुकाम है, इसका मुकाम सभी का मुकाम है और यह सिर्फ कौमी जुबान है और यह एक कौमी जुबान बन गई है । अभी हमारे दोस्त श्री नत्थी सिंह जी उधर से बोल रहे थे । उन्होंने श्री आनन्द जी के बारे में जोकि अंग्रेजी में बोले थे कुछ ऐतराजात किये । ठीक है, मैं समझता हूं कि दोनों की अपनी-अपनी राय है । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी एक से ज्यादा जुबानें जानना किसी भी दूसरी जुबान के लिये नुकसानदेह नहीं हो सकती है, किसी एक से ज्यादा जुबान जानना हमारे लिए किसी तरह से मुजिर साबित नहीं हो सकता । मैं तो समझता हूं कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा जुबानें जानता है तो उसकी हमें ज्यादा कद्र करनी चाहिए । एक से ज्यादा जुबानें जानने में या एक से ज्यादा जुबानें बोलने पर कभी किसी भी किस्म का ऐतराज नहीं होना चाहिए । वजह यह है कि यहां पर मुकाबले का कोई सवाल ही नहीं है । एक चीज हमने मानी हुई है, एक चीज को हमने राज-सिंहासन पर बिठा लिया है अगर उसका किसी दूसरी जुबान से मुकाबला किया जाये तो यह एक छोटी बात हो जाती है । मुकाबला तो बराबरी के लोगों में होता है, मुकाबला छोटे और बड़े में नहीं होना । इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हमने सिर्फ जुबान के मामले में बल्कि और तमाम ऐसी चीजों में अपनी फराखदिली, अपना बड़प्पन दिखायें यह समझ लीजिये कि अगर एक ही खानदान के अन्दर किसी के चार या पांच बच्चे है तो जो सब से कमजोर बच्चा होता है, आमतौर पर मां-बाप को उस बच्चे की सब से ज्यादा फिक्र होती है कि इसकी सेहत ठीक नहीं है और उसको बहादुर बनाने के लिये उसकी तरफ खास तवज्जह देनी पड़ती है । बाकी जो और बच्चे है इसका मतलब यह नहीं है कि मां-बाप को उनसे मुहब्बत नहीं होती है । इसी तरह से जुबान का भी मसला है । जो जुबान इस देश की जुबान है, इस देश की जितनी भी जुबाने हैं उनसे हमें उतना ही प्यार है जितना कि अपनी जुबान से । हमने जो भी जुबानें आठवें शैड्यूल में रखी है, जान-बूझ कर रखी हैं, समझ कर रखी है । यह हमारी जुबानें हैं, हमारे देश की जुबानें हैं, हमारे लोगों की जुबानें है और हमारी अपनी जुबानें हैं । जब यह हमारी अपनी जुबानें है, हमारे देश की जुबानें हैं तो इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए । उनको वही मुकाम मिलना चाहिए जो कि उनका है । इसमें यह नहीं कहना चाहिए कि कौन सी जुबान बाहर से आई है, किस जुबान पर बाहर की जुबान का कितना असर है, किस जुबान में बाहर के लफ्ज ज्यादा है और किसके अन्दर कम है मैं समझता हूं कि अगर इस बारीकी में जायेंगे, यह चीजें देखेंगे तो मुझे यकीन है कि हर जुबान में ऐसी कुछ न कुछ हमारे सामने दुश्वारियां आयेंगी । यह ऐसी चीजें हैं जिनको कि भुला देना चाहिए, जिनकी तरफ ज्यादा तवज्जह नहीं देनी चाहिए । हमें तो यह सोचना चाहिए कि कौन सी जुबान हमारे अपने देश की जुबान है, हमारे देश वालों की

जुबान है, हमारे देश की बातों से वह रिगाह खाती है, हमारे देश की तर्जुमानी करती है, हमारे देश की बातों के गीत गाती है और हमारे देश के मीठे बोलों को अपनाती है। अगर यह है तो हमारी हर जुबान जो आठवें शैड्यूल में है उसको पूरी अहमियत होनी चाहिए जो हम कौमी जुबान को दे देना चाहते हैं। यह मैं अर्ज करूंगा कि हम कौमी जुबान को हटाना नहीं चाहते हैं, कौमी जुबान अपनी जगह पर मौजूद है और उसकी अपनी अहमियत है और उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। अब आपका यह फर्ज है कि अपनी तरफ से इन जुबानों की भी मदद करें, उनको भी देखें कि जो आठवें शैड्यूल के अन्दर मौजूद हैं उनमें क्या अच्छाइयां हैं और आप क्या फायदे उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि श्री नत्थी सिंह ने उधर से बोलते हुए यह भी कहा था, एक दूसरे मुल्क की ओर इशारा भी किया था कि वहां पर जुबान का मसला इस तरह से तय कर दिया गया। ठीक है यहां भी ऐसा हुआ है कि जो उनकी सरकारी जुबान है वह उन की अपनी बन गई। उसके बाद जो रीजनल जुबानें हैं या और जुबानें हैं उनके लिए उन्होंने वही सब कुछ किया है जो करना चाहिए था। इस सूरत में मेरी गुजारिश होगी अपने देश में भी इन सब जुबानों को इसी तरह से आगे बढ़ायें, इसी तरह से उनकी मदद करें जिस तरह से दूसरे मुल्कों में यह तजरबे किए गए हैं। एक जुबान से ज्यादा जुबानें जानना एक बहुत बड़ी बात है। लोग तो एक से ज्यादा जुबानें सीखने के लिए बाहर जाते हैं। फिर मैं खुद भी अंग्रेजी में बोलता हूं। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी हमारी कौमी जुबान बन सकती है लेकिन आप यह सोचिए चाहे वह अंग्रेजी हो या दूसरी जुबान हो, अगर उसके अन्दर वे चीजें मौजूद हैं जिन से हम फायदा उठा सकें जिन्हें अपनी जुबान में ला सकें, अपने लिए बेहतरी की सूरत पैदा कर सकें तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इस ख्याल से कि वह दूसरे मुल्क की जुबान है, हम उस जुबान के जरिये से जो फायदा उठा सकते हैं वह फायदा न उठाएं। आज दुनिया के मुल्कों में अगर आप देखें मसलन जापान के अन्दर जाकर देखें। जापान के लोगों को अपनी जुबान इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा प्यारी है जितनी हमें अपनी कौमी जुबान प्यारी है लेकिन इसके बावजूद भी वे नयी जुबानें सीख रहे हैं। नयी जुबानों में यूरोप की जुबानें भी हैं, जर्मन है, अंग्रेजी है। वे सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि उन जुबानों के अन्दर जो साइंस और टैक्नोलोजी के लिए और दूसरे इल्मों के लिए नयी चीजें और अच्छाइयां मौजूद हैं, वे उनको असानी से अपनी जुबान में ला सकें और उससे फायदा उठा सकें। तो इसी तरह से हम अपने देश में भी अगर यह करना चाहते हैं तो इससे न किसी को यह ख्याल पैदा होना चाहिए कि हम अपनी सरकारी जुबान या कौमी जुबान का दर्जा किसी तरह से कम करना चाहते हैं। दरअसल हम उस दर्जे को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम उस जुबान को और ज्यादा रिच बनाना चाहते हैं, हम उस जुबान में जुबान में दूसरी जुबानों की जो कुछ खूबियां हैं उनको लेना चाहते हैं और उनको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।

इसके अलावा मेरा ख्याल यह है कि किसी भी मुल्क की जुबान हो, चाहे हिन्दुस्तान की हो या किसी दूसरे मुल्क की हो, कौमी जुबान का खास तौर पर सब से पहला मकसद और फर्ज क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से उसका मकसद आपस में मेल मिलाप का जरिया होना चाहिए, आपस में जो कुछ भेदभाव हो उसको मिटाने का जरिया बनना चाहिए, न कि ऐसी सूरत पैदा हो कि उस जुबान की वजह से या उस जुबान के जरिये कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिससे हमारे मेल मिलाप में फर्क पड़े या बाधा पड़ सके। हमें तो यह चाहिए कि उसको एक जरिया बनायें तमाम इख्तिलाफात को मिटाने का, भेदभाव मिटाने का जो आगे चल कर हमारी कौमी तरक्की में रास्ता रोकता है, रोड़ा बनता है, दुश्वारियां

[श्री खुरशीद आलम खान]

पैदा करता है । जुबान को, मेरे ख्याल से, हर जुबान को चाहे कोई भी जुबान हो उसको दिल जोड़ने का काम करना चाहिए, दिल तोडने का नहीं । अगर जुबान से दिल जोड़े जा सकते है तो वह जुबान सब से अच्छी है, अगर उस जुबान से दिल तोड़ा जाता है तो वह जुबान चाहे कितनी अच्छी हो वह जुबान अच्छी नहीं कही जा सकती है ।

इसमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जुबान के मामले मे और खास तौर पर कौमी जुबान के मामले में कभी तंगदिली से काम न ले इसलिए कौमी जुबान जो है वह हमारे पूरे कौम की जुबान है, कौम के हर आदमी की जुबान है, हर इंसान की जुबान है और वह हमारा भूला हुआ मुश्तरिका वरसा है जिसको हम सब हासिल करना चाहते हैं जिसमें बराबर के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, जिसमें हम सब का बराबर का हिस्सा होना चाहिए तो जब यह सूरत है तो कभी किसी को यह एहसास न होने दीजिए कि आप इसमें कम हिस्सेदार हैं या आपका हिस्सा कम है, अगर ऐसा होगा तो दूसरों को एहसास कमतरी पैदा होगी, उनको यह ख्याल होगा कि हम बराबर के हिस्सेदार नहीं समझे जाते हैं और मैं यह समझता हूं कि न किसी तरह से जुबान के लिए अच्छा हो सकता है, न कौम के लिए, न समाज के लिए और न मुल्क के लिए अच्छा हो सकता है । हमें तो यह करना है कि हमारी कौमी जुबान की तरक्की हो और होते-होते क्या हो अजब हो कि अगर हम तंगदिली दूर करने के बाद आपस के मेल मिलाप से इस देश में एक ऐसी जुबान का चलन शुरू कर दें जो हर एक को प्यारी हो, हर एक को आसान महसूस हो, हर एक का मतलब अदा कर सके, जो हर एक के लिए अपना दामन फैला सके और वह सूरत पैदा कर सके कि जब जुबान के मसले पर किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का इख्तिलाफ़, किसी तरह का झगड़ा बाकी ही न रहे और जब यह चीज पैदा हो जाएगी तो मुझे यकीन है हमारे देश में जो छोटी से छोटी बातों को लेकर इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे में या एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जो झगडे शुरू हो जाते है, उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जायगा, यह हम सबका फर्ज है और हम सबको करना ही पड़ेगा । ऐसा अगर हमने किया तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह मुहब्बत के स्रोत फूट निकलेंगे जो कभी न सूखने वाले स्रोत होंगे और जो ऐसे होंगे जिनमे हमेशा प्रेम और मुहब्बत की बाते होंगी, वह घुलमिल कर ऐसी जुबान का माहौल पैदा करेंगे, फिजां पैदा करेंगे जिसमें न कोई फर्क होगा, न भेदभाव होगा, न शिकायत होगी, न किसी को रंज होगा, न किसी को कभी महसूस होगी, न किसी को अपना हिस्सा कम दिखाई देगा । पूरे देश और समाज के लिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है और खास तौर पर जब हमें पता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी कौमी जबान को एक ऐसे पुख्ता तरीके से, एक ऐसे अच्छे तरीके से पूरे देश के माहौल पर डालने और लगाने की कि जिसमें लोगों को यह महसूस न हो कि साहब कोई नई जुबान हम पर लगाई जा रही है ।

जब हम एक ऐसे माहौल को पैदा कर लेंगे तो न किसी में इख्तिलाफ़ रहेगा और न कोई शख्स ऐसा होगा कि जो ऐसा कह सके कि यह जुबान हमारे ऊपर थोपी गई है । लेकिन साथ में मैं फिर अर्ज करना चाहूंगा कि हमें तंगदिली से काम नहीं लेना होगा । हमें हर जुबान से उसकी अच्छी बातों को लें, उसके अच्छे शब्द लें, हम हर जुबान मे जो उसके अन्दर नई-नई मालूमात है, नई-नई चीजें जो उसमें दरयाफ्त की गई हैं, वह अगर मौजूद हैं, तो उनको हमें अपनी जबान में पहुंचाना होगा और अपनी जुबान में ले जाना होगा और उसका जरिया यही हो सकता है कि हम एक से ज्यादा जुबानें सीखें और यदि

एक से ज्यादा जुबानें जानेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वे तमाम लोग अपनी कौम, समाज और मुल्क के लिए असैट साबित होंगे।

उनमें यह कोई बुराई नहीं, उनमें कोई कमी नहीं। वह अपनी जूबान से उतनी ही मोहब्बत रखते है जितनी कि दूसरें लोग रखते हैं। लेकिन साथ में मैं यह भी चाहता हूं कि उन जबानों से जो कि इण्टरनेशनल तरीके से मानी जा चुकी है, उनसे जो हम फायदा उठा सकते है उनसे पूरा फायदा उठायें, उनमें जो कुछ अच्छाइयां हैं उनको अपनी जबान में तबदोल करें, अपनी जबान में बनाएं और अपनी जबान को हम ज्यादा रिच करें और ज्यादा वसद पैदा करें और वह जबान ऐसी जबान बन जाए जो हम सब की जबान हो, सबको काबिले कबूल हो, न शुमाल और न जनूब तथा न मशरक या मगरिब का झगड़ा रहे, सब एक ही रंग हो, एक ही आवाज हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हू।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, I crave your indulgence, I am sorry I was called away by deputationists. My honourable friend, Shri Nathi Singh, referred to me and my speech. I would like to look up the record and see whether something has to be replied to. I reserve my right to do so.

SHRI ANANDA PATHAK (West Bengal): Sir, although the Bill is a step in the right direction the contents of the Bill and the Statement of objects and Reasons are disappointing for the people who speak other languages than Hindi and the languages which are specified in the Eighth Schedule as there is no provision for providing authorised translation of the Constitution of India into such languages which are not included in the Eighth Schedule. There is a number of developed and rich languages which have a rich heritage and culture and scripts of their own and which are understood and spoken by a vast number of people in India. These languages are not included in the Eighth Schedule of the Constitution for reasons not known to us and best known to the honourable Minister. That is why these people are again deprived of their right to have the Constitution in their own language. Thise is a very sorry state of things. The constitution of a country is treated as the highest law of the land. But if a vast majority of the people of the country, a vast majority of the citizens of the country, do not get an opportunity to understand the constitution of their country, how can you expect them to play their part as responsible citizens? Sir, in this country, for want of a correct language policy, frequent controversies among different sections of people and agitations are taking place from time to time. And the fissiparous elements in the country are taking advantage of the negative language policy of the Government to create troubles here and there. Therefore, it is high time that the Government pondered over their language policy. Without losing much time they should formulate a concrete and correct language policy which would fulfil the urge and aspirations of all linguistic groups in the country. They should be given the right to use their languages in the spheres of education, administration and all other spheres of life. This would ensure the unity and integration of our India. But I find that the language policy of the Government is creating dissensions and frustration among different linguistic groups. For example, the Nepali speaking people of this country have their own language and cultural heritage. They have been asking the Government for a long time to accord Constitutional recognition to their language. But this demand of theirs has been turned down time and again under one pretext or another. Similarly, there are people speaking Manipuri, Khasi, Bhojpuri, Maithili; Dogri; Kongani etc. etc. These languages have their own literature. People

[Shri Ananda Pathak]

speaking these languages are deprived of their opportunities in various walks of life because they are not included in the Eighth Schedule of the Constitution.

A few minutes back, an hon. Member from the other side said that Shri Anand did not speak in his own language. He is right. But the problem is that there is no arrangement for simultaneous translation of speeches made in these languages. Speaking for myself, it is very difficult for me to express my feelings forcibly in Hindi, Bengali or English. If I could have spoken in my own language, namely, Nepali, I could have expressed my feelings very well. Unfortunately, I am not given that opportunity because my language is not included in the Eighth Schedule of the Constitution. That is a real problem.

Further, I find that the Government have recently taken a decision about the languages to be used in the examinations for All India Services. It is a good decision. But what about people whose mother-tongue is not Hindi or any other languages incorporated in the Eighth Schedule to the Constitution. Sometime last year when I was speaking on the floor of this House, the hon. Minister had been kind enough to assure me that he was prepared to look into the difficulties of people speaking Nepali. Subsequently I wrote to him saying that Nepali speaking people are not given their right to answer papers for the All India Services examination in their mother-tongue. In reply to that, the hon. Minister was pleased to say: "I shall look into the matter and issue orders accordingly." Now what has happened? Only people speaking the languages in the Eighth Schedule of the Constitution can answer the papers in their mother-tongue. It is because of such policies that the linguistic minorities are agitating. I, therefore, urge upon the Government to make a provision for authorised translation of the Constitution of India in Nepali and other languages I have mentioned above. I would urge upon the Government to give Constitutional recognition to these languages by including them in the Eighth Schedule to the Constitution so that there will be no such anomaly in future with regard to any Indian language. With these words, I support the Bill.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, अभी हमारे साथी पूर्व-वक्ता ने दुरुस्त कहा कि कुछ ऐसी भाषायें है देश मे कि जिनकी मान्यता संविधान की अष्टम सूची में नहीं है । बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनकी मातृभाषायें ये भाषाये है । लेकिन उनका स्थान अष्टम अनुसूची में नही है । इसीलिए उनको ठीक से अपने को प्रकाश में लाने में दिक्कत होती है । उन्होंने नेपाली का ज़िक्र किया । यदि वह अष्टम अनुसूची मे उनका स्थान दें तो उन्हें अच्छा मौका मिलता अपने विचारों को व्यक्त करने में । उन्हें पूरी आज़ादी है उसके लिए मांग करने की । उसी तरह से मै आप के माध्यम मे इस सदन का और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैथिली भी बहुत धनी भाषा है । बिहार मे या उत्तरी बिहार में या यों कहें कि बिहार की आधी से ज्यादा आबादी मैथिली बोलती है, 5–6 करोड़ से ज्यादा लोग मैथिली बोलते हैं । उनकी मांग बहुत दिनों से रही है कि उनकी भाषा को अष्टम अनुसूची में स्थान दिया जाए, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने 30 साल के शासन में उनकी भाषा को मान्यता नहीं दी । अब मै मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह विधेयक तो हिन्दी अनुवाद के लिए आप लाये है तो इस बात पर विचार कीजिए कि मैथिली को मान्यता मिले संविधान की अष्टम अनुसूची मे ।

उपसभापति महोदय, यदि मान्यता नहीं मिलती है बोलने से,दरख्वास्त करने से,आवेदन करने से तब तो आप जानते है कि आप छोड़ देते हैं कि जनता आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करे । मैथिली भाषी लोग बड़े ही धैर्य के साथ बैठे है, उन्हें विश्वास है कि जनता सरकार मे यह

मान्यता मिल जाएगी और हमारे मंत्री महोदय जो मैथिली भाषी है अपनी मातृभाषा को अष्टम अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए इस विधेयक मे जो अनुवाद की बात होती है तो इस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर सरकार विचार करे। और भाषाओं के लोग उनके लिए बोलेंगे, लेकिन जिनकी मान्यता अष्टम अनुसूची में होनी चाहिए उनमे मैथिली प्रथम स्थान पर आती है।

जहा तक इस विधेयक के हिन्दी अनुवाद या अथोराइज्ड ट्रांसलेशन की बात है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हिन्दी के अथोराइज्ड ट्रांसलेशन में कैसी हिन्दी का प्रयोग हो। मैं यह इसलिये कहता हूं कि मैं आफिशियल लेंग्वेज कमेटी का सदस्य हूं। मैं दौरा करता हूं सारे देश का। हमारे मातहत होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कंपनी ला अफेयर्स, एजुकेशन आदि हैं। इन मंत्रालयो के विभागों मे जब हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हिन्दी में काम की जांच करते हैं तो वहां लोग बरबख्त सवाल कर देते हैं कि हिन्दी बहुत क्लिष्ट होती है। जैसे आल इंडिया रेडियो की बात कह देते है कि हिन्दी बहुत क्लिष्ट है। इस तरह के सवाल वह करते है कि हिन्दी की जो हवा आप वहा रहे हैं, जो हिन्दी वहां प्रयोग की जाती है वह हमारी समझ में नही आती है। हम लोग कहते है कि ऐसी बात नही है। मैं उधर भी जाकर कहता हूं कि आल इंडिया रेडियो की जो भाषा है वह क्लिष्ट भाषा नहीं है। ऐसी भाषा उनकी नहीं है जिसको आम जनता समझ नहीं सके। यह आपका सोचना गलत है। जो रोजमर्रा की हिन्दी है उसे हम इस्तेमाल करें और उसी हिन्दी में हम लिखें और उसे ही पढ़े। उदाहरण के लिये मैं कहता हूं कुछ ऐसे शब्द है अंग्रेजी के, जिसको हम कहते हैं हिन्दी में डाइजेस्टिड हो गये है जिनको हम चाहने पर भी हटा नहीं सकते, जैसे, कोई शब्द है। 99 प्रतिशत जनता हिन्दी मे इसको जानती है और इस्तेमाल मे लाती है। ऐसे ही 'टिकट' 'स्टेशन' 'बस' आदि ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जो यहां हिन्दी में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें आम जनता समझती है। इसीलिये अनुवाद की जब बात आती है अथोराइज्ड ट्रांसलेशन की बात आती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है आप कीजिए लेकिन हिन्दी मे जो अनुवाद हो उसका क्या स्टेंडर्ड हो इसके बारे में भी सरकार को साफ हो जाना चाहिये। यदि पंडित लोग संस्कृटाइज्ड हिन्दी, क्लिष्ट हिन्दी को अपनायें तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी में भी हिन्दी के बहुत से शब्द डाइजेस्ट किये है और दूसरी भाषाओं ने भी हिन्दी के शब्द डाइजेस्ट किये है– जैसे-जंगल है। जंगल हिन्दी शब्द है, भारतीय शब्द है लेकिन जंगल अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है, उपन्यासों मे। ऐसे ही 'बाजार' शब्द है। यह भी हिन्दी शब्द है लेकिन अंग्रेजी में नावलों में उपन्यासकारो ने इस्तेमाल किया है। ऐसे बहुत से हिन्दी के शब्द है जिन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है। विस्टन चर्चिल जिसने एक फौजी के रूप में अपनी जिन्दगी शुरू की और जिन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला। भाषा को लेकर के उसने दो शब्द हिन्दी के सीखे जिसे उसने अपने उपन्यास में इस्तेमाल किया। एक है 'मारो' जिसको अंग्रेजी मे कहते है 'किल' और दूसरा शब्द है 'चलो' जिसको अंग्रेजी में कहते है 'गो' इन दो शब्दों को चर्चिल ने इस्तेमाल किया––किल–मारो और गो-आगे बढ़ो। आपने यदि उनके नावल पढ़े होगे तो आपने देखा होगा इन शब्दों को।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यदि आप अनुवाद की बात करते हैं अथोराइज्ड ट्रांसलेशन की तो ठीक बात है। यह होना चाहिये इससे कोर्टस में आसानी होगी, सहुलियत होगी। जब यह प्रचलित भाषा हो जाएगी तो सब लोग उसे इस्तेमाल करने लगेगे लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि जो भाषा हो वह साधारण भाषा हो। मै अंग्रेजी का ही उदाहरण देना चाहता हूं। थामस हार्डी की अंग्रेजी

[श्री शिव चन्द्र झा]

सिम्पल है । उसने एक किताब लिखी है 'रिटर्न आफ द नेटिव' । आपने भी इसे पढा होगा । इसकी शैली बड़ी सुन्दर है । इसी प्रकार चर्चिल को लीजिए । इसके नावल भी सिम्पल शब्दावली से भरे हुए है । एच० जी० वेल्स की अंग्रेजी लीजिए । उन्होंने भी सिम्पलीफाइड अंग्रजी में लिखा है, साधारण अंग्रेजी में लिखा है । अमेरिका के लोग अंग्रेजी को सिम्पली फाइड कर रहे है--जैसे, प्रोग्राम में उन्होने एक 'एम' लगाना शुरू कर दिया है और 'नाईट' की स्पेलिंग 'एन आई० टी० आई० कर दी है । काम चलाऊ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना शुरु कर दिया है । इसलिये जब अनुवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है संविधान के अनुवाद से ही नहीं सरकारी कामकाज और सरकारी कागजात की भाषा से भी । इसके लिये हमें गौर करना चाहिये कि उस भाषा का स्टेंडर्ड क्या हो । मेरा यह कहना है कि जो साधारण भाषा हो, साधारण हिन्दी हो जिसे लोग आसानी से समझ सकें और आसानी से इस्तेमाल कर सकें उसी में हम ट्रांसलेशन करें ।

मेरे मित्र ने अभी तुलसीदास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने साधारण जन भाषा मे रामायण को उतारा । आप जानते हैं कि जन भाषा में रामायण को उतारने के लिये कितने विरोध का सामना करना पड़ा । पंडितों के मन में यह बात थी कि राम की कहानी हिन्दी मे लिखी जाएगी तो जुल्म हो जाएगा । क्या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हिन्दी में उतारे जायेंगे ? यह तो राम की तौहीन है । आखिर में उनकी पाड़ुलिपि चुरा ली गई । उन दिनों भी साजिश चली कि राम की कथा बोल-चाल की भाषा में कैसे लिखी जा सकती है । इसलिए तुलसीदास जी ने जो पाण्डुलिपि लिखी उसकी रक्षा के लिए दो दो पहरेदार लगे हुए थे । उनकी पाण्डुलिपि की रक्षा के लिए हर वक्त दो पहरेदार मौजूद रहते थे ताकि उसकी चोरी न हो सके । जब तुलसीदास जी को ख्याल आया और उन्होने देखा तो पता लगा कि वही दो पहरेदार हैं और वे दोनों राम और लक्ष्मण ही थे । इस प्रकार से कहानी चलती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आम सरल भाषा के रूप में हिन्दी का विकास किया जाना चाहिए । जो काम तुलसीदास जी ने किया है वही काम आपको करना है । हिन्दी का उसी धरातल पर विकास होना चाहिए । आपने हिन्दी में अनुवाद करने का सिलसिला चलाया है । मैं चाहता हूं कि अनुवाद साधारण भाषा में किया जाना चाहिए । संस्कृटाइज हिन्दी लोगों की समझ में कम आती है । उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हू कि हिन्दी मे पहले संस्कृत-निष्ठ भाषा में कविताएं की जाती थी, जैसे --

'दिवस का अवसान समीप था,
गगन कुछ लोहित हो चला ।
तरु शिखा पर अब राजति,
कमलनि कुल वल्लभ की प्रभा ।'

यह हरिऔध जी की कविता है । इसी प्रकार से एक दूसरी कविता भी है --

"तू पूछ अवध से राम कहां,
वृन्दा बोलो घनश्याम कहां,
ओ री उदास गंडकी,
बता विद्यापति कवि का गान कहां ।।"

यह दिनकर जी की कविता है । यह साधारण जनता की हिन्दी है । इसलिए मेरा कहना यह है कि साधारण बोलचाल की हिन्दी में ही अनुवाद का कार्य किया जाना चाहिए और इसी रूप में हिन्दी का विकास किया जाना चाहिए ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि भारत की जितनी भी मान्य भाषाएं हैं उन सब में संविधान का अनुवाद किया जाना चाहिए । लेकिन इस बात का ख्याल किया जाना चाहिए

कि सभी भाषाओं में अनुवाद करते समय आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाय जिसको सब लोग समझ सकें। संविधान का अनुवाद सभी भाषाओं में अथोराइज्ड रूप में हो, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि अन्तिम सूची में आप मैथिली भाषा को भी मान्यता प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का फिर समर्थन करता हूं।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to take part in this discussion. The object of this Bill is to help the people of India and also to develop all the national languages and all regional languages of our country. But Sir, some of the learned Members of this House have clamoured their anti-English zeal and passion to impose Hindi on other people. On behalf of the D.M.K. party to which I have the honour to belong, I want to express my sentiments on this issue. One of the arguments put before this august House by some of the Members is that all the statutes and laws should be brought in Hindi and also other languages in order to replace English. Sir, I want to submit before this House that English is not a foreign language to our country. My learned friend, Mr. Khurshed Alam Khan, said in this House that English shall never be the national language of our country. He should not confuse the national language with the official language. If we say that English can never become the national language of our country, then I want to put some questions. The official language of Nagaland is English. Do you mean to say that Nagaland is not a part of our country? Similarly, the official language of Mizoram is English. Do you mean to say that Mizoram is not a part and parcel of our country. I also want to say that the mother tongue of the Anglo-Indians, who are also the citizens of this country, is English. Then do you say that the Anglo-Indians are not our citizens? Are they not the citizens of our country? So, we must see what has happened after independence in our country. Our learned friend demanded that Nepali should be included in the Eighth Schedule, another Member wanted that Maithili should be included in the Eighth Schedule. I welcome that. Like that, English should also be included in the Eighth Schedule as a national language of this country because it is a language spoken by the people in some States, and also by the Anglo-Indians. Instead, you are saying that English is a foreign language, those who are opposing Hindi are welcoming a foreign language. We cannot accept that argument. If you say that English is a foreign language to the people belonging to the Hindi belt, to the people belonging to Hindi is a foreign languages to us, the Uttar Pradesh, then I want to say that Hindi is a foreign languages to us. the Tamilians. It is a foreign language to us. You learn that language Hindi, with your mother's milk. But we have to study that Hindi language which is foreign to us. You say that English is a foreign language. Hindi is also a foreign language to us. My mother tongue is Tamil. English is a foreign language and Hindi is also a foreign language to us. You say, "No, no. The language is spoken by a majority of people in India. Hindi is spoken by a majority of people." I want to counter that argument. According to the 1971 Census, out of 570 million people, 162.5 million speak Hindi. This is below 40 per cent. Which is the ratio often quoted by our hon. Prime Minister. Even that 40 per cent, according to your argument, is not evenly distributed throughout the country, from the Himalayas to the Cape Comorin. That 40 per cent is confined to some States. That 40 per cent is confined to Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and some other States. So, you cannot say that this is the language of a majority of the people. So, we

[Shri V. Gopalsamy]

have to see one thing. That may be spoken by 2 per cent or 3 per cent. But at the same time, you must realise that the advantages and disadvantages should be evenly distributed to all. To take shelter under the principle of majority is a mockery of democracy. You cannot cite the Constitution. You cannot take it for granted as *fait accompli* that according to the Constitution, according to article 17, Hindi is the official language. You cannot say like that. We oppose that article. If you want a true democracy, then article 17 of the Constitution should be deleted. In its place, we must see that all the national languages of our country are given the status of official languages. Till then, English alone should continue as the official language.

Then, you may put a question: What will be the link language of this country? Yes, the link language should be decided by the people, not backed by the Government. It should be sponsored by the people. It should be sponsored, and it should be spontaneously accepted by the people. And in due course, it will develop. You give equal opportunity to all the regional languages, to all the national languages. Then the time will decide as to what should be the link language of this country. I also want to say that India is not a country at all. It is a sub-continent. It is a country of so many nationalities. It was not a country before the Britishers came. I want to cite none other than the present President of our country, hon. Shri Neelam Sanjiva Reddy, that not even during the times of Ashoka nor of Akbar, India was politically one. When the Britishers came, with their might and skill, they moulded different units of this country into a single political entity. So, English has united this country. English has united so many nationalities, so many cultures, so many traditions, so many languages and so many races. All these have been united by the English language. So, it has got the cementing force When I was hearing the arguments of some of my friends here, I was astonished to see how they are interested in spreading Hindi not only in India but throughout the world also. It was said that when Hindi was spoken in the United Nations, it was welcomed by so many countries and that it would become the international language. I want to say that you can have the North Pole and the South Pole meet but you can never enrich that language called Hindi. I am not inimical to that language. I want to quote a great jurist, the former Chief Justice of the Bombay High Court, and once a Minister of the Central Government, Mr. M. C. Chagla, who said that it will be a very difficult task to translate all statutes and laws into Hindi and that it will only open up a Pandora's box. There are 47 dialects in Hindi they say. The Hindi spoken by a U.P. walla is not understood by a man from Bihar. Yet you want to enrich the Hindi language. If you say that you want to raise the Hindi language to the international level, I want to submit that if at all there is a language which deserves to be the international language, it is our language. I have got a right to say this. These are the facts. This has been there for the last two thousand or three thousand years. If anybody learns that language, drinks deep in the nectar of that language, then anybody will accept that it is a classical language, it should be the language of the masses and it should be the international language. This is the fittest language and this is the hoary language.

You may say that these people from the South, these people from Tamil Nadu, are always for separation, they are always parochialism, they are for chauvanism. This is the usual brand of words used against us for attacking us. We are not chauvinists, we are not parochialists and we are not for separation. Even two thousand years back our Tamil scholar preached the unity of the gospel.

'Every land is the same, everybody is a friend.'

Even today it is the same thing. This gospel was preached about two thousand years back by a Tamil scholar. We are not parchialists and we are not separatists.

When our country was attacked in the year 1962, when the cannons roared in the Himilayas, our late lamented Tamil leader, the glorious leader, the founder of the D.M.K., our revered Anna, gave a clarion call to Tamil masses to defend our country. So also in the year 1971, when there was the Bangladesh war, when we had the encounter with the Pakistan Army, my leader, our Party leader, Mr. Karunanidhi, when he was the Chief Minister of the Tamil Nadu State, gave a call to mobilise resources and we contributed Rs. 6 crores to the National Defence Fund, an amount more than that contributed by any State of our country. So, we are not parochialists. But, at the same time, we must read history. When you want to impose the Hindi language, when you want to impose one language over others, you must see that it is undemocratic. The individuality and originality of all the nationalities should be protected in our country. Then only the real democracy can exist in our country. If you want to impose, then I want to tell you that you are sowing the seeds of separation. If you want to dominate, then you are sowing the seeds of balkanisation. I want to quote an example from history. The famous historian, Arnold Toynbee in his book, "History of Civilisation", has clearly pointed out that one of the causes for the downfall of the Roman Empire, the great Roman Empire, was the language policy. When Rome ruled from the banks of the Nile to Rhine, when Cicero was boasting to the Senate that all the roads were leading to Rome, the Romans wanted the Latin to become the official language. Latin was made the official language of the Roman empire Then the city states of Greece, the Greek city states, revolted against this language imposition. There may be other reasons also for the downfall of the Roman empire like the debauchery of the senators and the kings and the invasion of the Huns. But one of the reasons for the downfall of the Roman empire was her language policy. This is what has been said by Mr. Arnold Toynbee.

So we must be very careful in our language policy. If you want to dominate, then you are not striving for the unity of this country. One of my learned friends told about Russia but you must realise that even in Russia, after the great revolution, Comrade Lenin clearly stated: "There should not be any imposition of one language on other languages; there should not be any domination of one nationality on the others. If anybody wants to dominate, if anybody wants to impose, then I defend the right of self-determination." This has been clearly stated in his book "On the Language Question". So you cannot cite Moscow. I can cite Turkey where Mustafa Kamal Pasha wanted to liberate his language from the imposition of other languages.

[**The Vice-Chairman (Shri Ghanshyambhai Oza)** in the Chair]

I can cite Ireland where De Valera fought for his language from the domination of English language.

So, seeing the past and visualising the present situation, you must realise that there should not be any imposition in our country. At the same time I want to submit before this House that if you want to impose, if you want to cajole, if you want to coerce under the shelter of majority, then we will fight till the last. We will strike at your very roots and we will definitely see that Hindi is not imposed. Our party DMK will carry on its relentless fight and relentless agitation, whatever the consequences. Don't forget the fate of Europe. If you want to impose Hindi or a particular language on the other languages and on other nationalities, then the fate of Europe will be repeated in our country.

[Shri V. Gopalsamy]

With these words, Sir, I conclude.

SHRI B. N. BANERJEE (Nominated): Sir, at the outset, I say that I support the Bill with some observations. Sir, if you look at the Statement of Objects and Reasons appended to the Bill, it is said:

> "Authorised translations of the Constitution and the various Central Laws in Hindi and other languages included in the Eighth Schedule of the Constitution will be extremely useful in promoting the use of Hindi and other languages in proceedings in courts."

Sir, I would say that this is one of the very minor objects and reasons for the Bill. The more important purpose of law like this or the authorised translation of the Constitution in Hindi and other languages included in the Eighth Schedule would be to enable people who do not properly understand English and who are more familiar with their mother tongue and Hindi also, to understand and appreciate the various provisions of the Constitution. Sir, this authorised translation of the Constitution in various languages including Hindi would be more useful if viewed from this angle than what is given in the Statement of Objects and Reasons that it will be useful for use in the courts. As you know, now-a-days, the business in many of the State Governments is carried on in the regional languages and Hindi and, Sir, you will also know that upto the higher secondary standard or even at the university stage in most of the universities, the recognised language is the regional language. If that is so, it is all the more necessary that the students who are studying the Constitution or the political science, must have the authorised translation of the Constitution in Hindi and also in the language used in that particular region as included in the Eighth Schedule of the Constitution.

Sir, from this point of view, this is a very useful Bill and I congratulate the hon. Home Minister for introducing this Bill. Sir, I cannot improve upon the speech of the hon. Member, Shri Jha, as to the type of language that should be used while translating the Constitution into Hindi and other languages. He has made it very clear that the language used must be such which would be understood by the people. We know that when the various Departments of the Government of India started translating the various English terms in use into Hindi, it gave rise to a horrible situation. The people could not understand the many expressions used at the railway stations, post offices and other places. Possibly, they were translating these things from the dictionary or making them highly Sanskritised or something; I do not know. But the right approach is the approach which the hon. Member, Shri Jha, has mentioned.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): Sir, Mr. Banerjee is an expert on legal things and he has also held very important positions. He knows the legal complications. As far as the terminology is concerned, do you think that the ordinary people who do not have any grounding in English, particularly the legal English, the English of the courts, the legal terminology, do not find it difficult to understand such expressions? Even people with Master's Degree in English may not be able to understand such legal expressions. This question is about terminology. I would like to know your opinion whether the expressions should be translated into the other languages or the same English expressions should be kept. Your opinion would be helpful.

SHRI B. N. BANERJEE: The point that I was making was different. I am saying—I will come to your point later on—that when you translate a

particular statute into Hindi or Bengali or any other language mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, your objective should be to see that the translation should have expressions which are understood by the people. This has been pointed out by Mr. Jha. He recited two verses, both in Hindi, one by Prof. Dinkar and the other by some other person. Even a person like me who does not understand Hindi much, could feel that the language used by Prof. Dinkar was more understandable. Even a person like me who does not claim any special knowledge of Hindi could understand it.

As to the point mentioned by Dr. Ram Kripal Sinha, there are expressions which are used in the legal terminology. For this, they will have to find a proper translation and as Mr. Jha has said, it may perhaps be better to keep the same expressions that are used and are well-known in English, in legal terminology, than try to make a translation of the same into Hindi or Bengali or some other language, which will not be understood even by educated persons I am pretty sure that even in respect of the translation of some of the Central or State enactments which have been done, the original expressions have been retained in the translated versions. This is necessary because you will have to assimilate certain other expressions from other languages which have become a part and parcel of your own language. Otherwise, it will not be understood by the people.

I now come to the next point. If you read the Financial Memorandum, you will find that except for an expenditure of Rs. 75,000, they say that no other expenditure is involved in this. The expenditure is out of the question. You know how many lakhs are spent in an election. But this is the supreme law of your land, the Constitution of our country. For this purpose, your objective should be to have a proper translation of this document and you should not grudge any expenditure that is necessary.

But, Sir, by that I am not suggesting that you waste your money. They have said that the expenditure would be roughly about Rs. 75,000. Let them have it. If they want to spend more money, certainly, we, the Parliament, would not grudge it, but what I am asking is this. How long will they take? We have been here for a very long time. There was a Hindi version of the Constitution sponsored by Rajenbabu. Even the Government of India had their Hindi version of the Constitution. I would like to ask the hon. Home Minister, although it is not the subject now, how many prints of the Constitution of India which was adopted in the year 1950 have been published so far? Even today if you ask the Ministry of Law or the Publications Division to provide you with a copy of the Constitution, Hindi version, you will possibly get a copy which was printed in the year 1970. That is the position and I do not think I can be contradicted on this. I am asking the Rajya Sabha Secretariat here to get me a copy of the Hindi-version Constitution. Let them produce it. I am sure, they will not be in a position to do so. Then, there have been so many amendments to the Constitution. I think about 44 or 45 amendments have been there. None of them have been translated. So, it is a very very huge programme. You have to translate it not only in Hindi but also in all the languages mentioned in the Eighth Schedule.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: There will be many more amendments to the translated versions.

SHRI B. N. BANERJEE: Therefore, it is no good simply to pass a law like this. We are going to pass the law here today and in the course of a day it will be sent to Lok Sabha.

[Shri B. N. Banerjee]

The object may be laudable, but I am telling you, I will be here for a few more years and I do not think the translations will come even during my tenure here, I am pretty sure of it. The Hindi version may come, but the other versions will not come.

Sir, here it is necessary to mention another factor. From the Financial Memorandum you will see that this work will be done by the translation wing of the Legislative Department of the Ministry of Law. They are very competent people, very hard worked people. If they go to Mr. Patel for more staff, he will say, no, no, you are already overstaffed. Now imagine the translation work they have to do. Previously, you have also passed a law for translation of the Central laws into other languages. Forgetting the other laws if you think only of the translation of the Constitution in Hindi and in all the 14 or 15 languages mentioned in the Eighth Schedule, I am sure, the Law Ministry would not have the necessary number of men at present to do this work within a reasonable time. This aspect has to be rememberd I am not talking of the other Central Acts, I am talking of the Constitution only.

Then there is one more aspect of the question. As I said, the translation wing of the Law Ministry consists of the translators with legal background and also, if I am not wrong—my knowledge on the subject is rather rusty—they may consist of people with judicial experience. But, Sir, nowadays you do not have a body like the one, what was called previously the Official Language Legislative Commission. That was a high-powered body. It consisted of not only the translators, or the civil servants, but the retired High Court Judges, jurists etc. and they ultimately vetted the translation of the Central Acts, etc. That is gone.

Therefore, Sir, the translation will be provided. I am not questioning the competence of the persons who will translate. But nevertheless you are translating the Constitution and you will have to see that Constitution is properly translated. Sir, if I say something in a speech here today, not much importance may be given to it. But if the same speech is made in this House by Shri Bhola Paswan Shastri, or Prof. Ranga or Shri Bhupesh Gupta, or Shri Kamlapati Tripathi, that is given more importance. Why? Because it has come from Shri Bhupesh Gupta, or Prof. Ranga or Shri Tripathi. I might have used the same language. Therefore, it is also necessary to see who ultimately okays the translation. In this connection, I have a suggestion to make. When you finally publish this Constitution as the 'authorised' Constitution so far as Hindi and other regional languages are concerned, it must have to be seen—I am not suggesting a full-time standing body—by an *ad hoc* body consisting of jurists and persons who are familiar with the particular language in the Constitution. This will be necessary so that they can see that the translation has been properly done.

PROF. N. G. RANGA: And belonging to all parties.

SHRI B. N. BANERJEE: I am not taking it as a party issue. So, that is very necessary. (*Time bell rings*). You will give me two or three minutes because I seldom speak. I don't think I take ten minutes' time in a Session.

The next question is, it has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons that a Hindi translation of the Constitution of India was prepared under the guidance of the late Dr. Rajendra Prasad, the then President of the Constituent Assembly. I would caution the Translation Wing of the Law Ministry that this particular document—though it is not an

authentic version as is also mentioned in the Statement of Objects and Reasons—is a document of historic value and is associated with the name of Dr. Rajendra Prasad. Therefore, while translating the Hindi version of the Constitution, they may not unnecessarily tamper with the language used in that particular translation which had Rajen Babu's blessings.

One last point and I have done. There may be a wrong impression in the House that possibly the various translations of this Constitution in Hindi and various other languages have much legal value. I would tell you that the authorised translation is only an 'authorised translation' and not an 'authorised text' of the Constitution. The Constitution was passed in English language. Therefore, Sir, what is the authoritative text if there is a dispute? You will have to refer to the Constitution as adopted—and that is in English language. This is only an 'authoritative translation' thereof. There may be a wrong impression in the minds of some people that whenever there is a discrepancy or difference between the two, there will be harmonious interpretation. This is a wrong impression. If there are two authoritative 'texts' of a document and if there is a discrepancy between one and the other, then the rule of harmonious interpretation may come in. But here they have deliberately used the words 'authoritative translation'; they have not even used the term 'authoritative text' as they have used in section 3 of the Official Languages Act, or in sub-clause (iii) of Art. 348(1) of the Constitution. What I mean to say is that I am not enamoured about whether it is English or Hindi. This is the Constitution of our country. I must know what the Constitution is and, therefore, I am telling my friends that the authoritative version of the Constitution still remains to be the English version which was adopted. But these documents are very much necessary because they will enable the courts of law and the students and other persons who do not know English and the other languages to know, in their own mother tongue, what the Constitution is of his or her country.

PROF. N. G. RANGA: Sir, we are in favour of this Bill limited as it is in its objects. But then we have to be extremely careful about the relevant points made by Mr. Banerjee who has had great experience with the work of this House as the head of the Secretariat and who himself has been an eminent lawyer. How soon are they going to get this translation made is a very important point. It has taken more than thirty years for this Government to think of translation. Are they going to limit their efforts to Hindi alone? If that is so, they will be treading on a very dangerous ground and a very sensitive ground also.

My friend from Tamil Nadu belonging to the D.M.K. has given a taste of the strong feeling in South India today. Language, Sir, is a very sensitive subject as every one knows, especially for politicians and also for pundits. People can be progressive with regard to many other things much more easily than when it comes to language. For instance, my own language Telugu is very close to Kannada. These two are so much allied that we are able to read each other's script. But at the same time we are foolish enough, or reactionary enough, or conservative enough not to make a few changes in either of these two scripts to turn it more or less into the same script for both of us. A few turnings only have to be made and yet all this time we have refused to do it. Sometime ago Mr. Hanumanthaiya, when he was the Chief Minister, took some initiative and wanted the pundits on both sides to come to some agreement. They could not reach any agreement at all. Thereafter also another effort was made. I was trying to persuade these pundits on either side to reach some agreement but they would not so

[Prof. N. G. Ranga]

much so that these two languages and the 8-9 crores of people speaking in these two languages are just being kept apart by this barrier, the terrible barrier of language as far as these Kannadigas and Andhras are concerned.

The Telugu-speaking people are about 4½ crores and the Kannadigas also are 4½ crores. These 9 crores of people at least can be brought together through literature, through their culture by making these few changes. Then what is it, Sir, that separates them so far as the substance of the language is concerned? More than half of the words are Sanskrit words. Another 25—30 per cent are the original Tamil words. Only 20 per cent are either original Telugu or original Kannada. And they have been kept apart by introducing not only Sanskrit grammar but what is known as Vibhakti Parichaya.

There is a word called Kashta. If you simply say Kashtamu it is Telugu. But Kashta is Kannada. Similarly, take Santosh It is a Sanskrit word. If it is Santosha it is Kannada but if it is Santoshamu it is Telugu. And yet these people are so wonderful as not to agree to make these few changes. Fifty words in ordinary parlance on the Kannada side if accepted by the Telugus, they would be understood by the Kannadas and vice versa. Fifty ordinary words of ordinary use by Telugus if adopted by Kannadigas, the Kannadigas would be able to understand Telugu. Yet we have not been able to achieve this much compromise. It is this kind of a dangerously sensitive subject that our Hindi fadists have been playing with for a long time.

I have no objection to our Constitution being translated into Hindi, but why have they put it here as "Hindi or other languages"? Why that dangerous word "or"? When it comes to the Explanation it is "Hindi and other languages". Who was responsible for this blunder? Who drafted the first and who drafted the next? Are they the same? Did the Minister concerned and his Secretaries and all those people concerned pay any attention at all? There is such a dangerous sort of implication here.

For this purpose they want to set apart Rs. 80,000 or whatever it is. But it is going to be eight lakhs of rupees, as Mr. Banerjee has already warned you. With these Rs. 80,000 you would not be able to do it. And not so soon whether it is Rs. 8 lakhs or Rs. 80,000 or whatever it is. If you are going to translate it into Hindi, to start with, why not follow another and a more economical method of asking your Hindi-speaking States like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Haryana to do it and leave it to them? Let them make a combined effort to translate it into Hindi and then ask the Gujarat Government to translate it into Gujarati. Similarly you can ask the Tamil Nadu Government to translate it into Tamil, the Andhra Pradesh Government to translate it into Telugu, and so on. Also you have a number of States interested in their local languages. Why not enlist their co-operation and make a joint effort? That would be a statesmanlike approach towards this problem. Instead of doing that if you make this kind of a thing, I think it would give room for suspicion—as has been voiced by my friend on behalf of the DMK—that you people from the North who are dominating for the time being, for whatever reason it may be, wish to impose Hindi on everybody else; therefore, you exploit and utilise the opportunity that you have got in leading the Government of India only to sponsor and further the spread of Hindi, its popularisation, its authority and status by getting the authorised translation of the Constitution in Hindi itself, to start with. Why should the first effort be made in Hindi? Why should not this effort be made simultaneously in all the other languages?

If that is your wish, then why are you so parsimonious or miserly in using your words? Why did you not take time by the forelock and say here in this Bill itself, "Hindi and other languages simultaneously"? Only two or three more words would have done. It seems this country and its languages are under a bad star because, somehow or other, whenever they want to do a good thing also they go about it the wrong way and give room for all these misunderstandings.

I for one may tell you quite frankly that I am not in favour of Hindi domination. Nobody is in favour of Hindi domination. Any Hindi-speaking man to whom Hindi is his mother tongue, if he is a wise man he would not really be willing to say that he would like his mother tongue dominate over the whole of India. But a time would come, just as English has come to be more or less our national language till now, then Hindi may also grow into a national language. But you are not going to achieve it by simply talking about it. It is all right for me, a non-Hindi-speaking man, to say, "Yes, Hindi should become the national language" but it would be extremely unwise for a Hindi-speaking man, for a man to whom Hindi happens to be his mother tongue, to say that Hindi should become the national language. All our languages are national. If he goes about saying this, he will be accepted by others. All of them should be treated with the same respect, with the same sentimental attachment. Otherwise, he is likely to be dismissed.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): There was a time when Hindi was propagated more by the Southerners. Now it is because...

PROF. N. G. RANGA:...of their madness...

SHRI L. R. NAIK:...that all these things are happening.

PROF. N. G. RANGA: Quite true. It is because of this weakness and madness, some kind of reactionary trend which has been there—reactionary trend which has been lurking in their mind—that these people have created trouble for us. Sir, as my hon. friend has reminded us, it was Rajaji who introduced the Hindi Swabodhini in South India through Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. Under the inspiration of Mahatma Gandhi, we all tried to learn a bit of Hindi when we were in jails, with the help of that Swabodhini. The same Rajaji was obliged later on, thirty years later, to turn against these imperialistic Hindi-wallas and say: "Nothing doing. English must be our link language. In addition to that, if you are going to have Hindi, by all means, have it, we would have no objection." Why was he obliged to take that stand? I was myself present at a great meeting held in Patna when Rajaji had to address more than a lakh of people in 1960. The Hindi fadists began to demand that he should speak to the people only in Hindi; they did not allow him to proceed further. He said, if he was going to be forced in that manner, he was not going to speak. He had to abandon the meeting. Next day, when we went to Banaras, by that time, they had become a little wiser. Then they came and captured our platform and said, "We are not going to allow Rajaji to speak in English. He must speak in Hindi. If he cannot speak in Hindi, we would have no objection if he speaks in Tamil." When I started speaking in Telugu, they would not allow me. Why? Because they did not know whether it was Telugu or Tamil or Kannada or anything else. And from that moment onwards, Rajaji was able to give the warning that this kind of Hindi imperialism would not do and ever since then there has been a terrible reaction in the South. It must be understood that the learning of Hindi was making very rapid progress in the South. We all took it as a kind of national duty to learn Hindi, when Bapuji was

[Prof. N. G. Ranga]

alive, and afterwards also, in our schools. But, after that campaign which was launched by—I need not mention the names of the sponsors of the movement—the leaders of that movement, reactionary movement, anti-national movement, there has been a great deal of reaction in the South. Nevertheless, Sir, people in the South are sensible enough to allow their children, more and more of them, to learn a little of Hindi. We are learning it. But it would take some time. North India has got to make a contribution through wisdom as well as through financial support, which it has been failing to do. And till then, they must wait—and wait patiently and in a sensible manner. Instead of that, I have seen from time to time some Members from this side, some Members from that side, in this House as well as in the other House—they are not ordinary folk; they are Members of Parliament having been elected by various methods—begin to display such reactionary spirit in favour of Hindi and impatience in regard to other languages and, what is more, hatred towards English. They themselves know English, but they seem to be too parochial to say that English should not be spoken by all those people who know Hindi, or some other language. Now, it is these people who are our national enemies, let me tell you. I need not expatiate any more. Andhra is not going the way AIADMK or DMK so far as Hindi is concerned. But Andhra, Karnataka, Kerala—these States in the South are likely to go that way if our Hindi friends do not exercise the necessary degree of patience as well as wisdom, affection twoard.s, as well as appreciation of, these people for whom Hindi is not their mother-tongue.

Therefore, Sir, in conclusion, may I expect the hon. Minister who has sponsored this Bill—although I have not myself moved that amendment—to take your special permission and permission of the House to make the small amendment "Hindi and other languages" instead of "Hindi or other languages" so that it would remove the cause for suspicion.

Thank you.

श्री सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूंगा मगर दो चीजें इसमें मुझे कहनी है। एक तो यह है कि इस सदन में मैं सुनता आ रहा हूं कि कभी किसी भाषा में बोलें, तो ऐसा महसूस होता है कि हम किसी भाषा के साथ घृणा करते हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी भाषाओं की तरक्की हो और सभी भाषाओं का इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यक्रमों मे हो और यहां माननीय सदस्य कहते हैं कि हिन्दी का इम्पोरिलिज्म है। यह मेरी समझ में नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत ही खुश होता अगर मिस्टर गोपालसामी तामिल में भाषण देते। इस सदन के लोग भी बहुत खुश होते और उनको तामिल भाषा में सुनने का अवसर मिलता। यह कहना कि किसी भाषा के साथ नाइन्साफी हो रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कोई माननीय सदस्य समझता है कि किसी जुबान की तरक्की नहीं हो रही है, उर्दू की तरक्की नहीं हो रही है तामिल की तरक्की नहीं हो रही है, बंगाली, गुजराती की तरक्की नहीं हो रही है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तभी हो सकती है जब हम यहां पर उस भाषा को इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि हर भाषा की तरक्की हो, हिन्दी की तरक्की हो, गुजराती की तरक्की हो, बंगाली की तरक्की हो, तामिल की तरक्की हो, पंजाबी की तरक्की हो, जितनी भाषाएं हैं सब की तरक्की हो, यह तभी हो सकती है जब हम इन भाषाओं का रोजमर्रा की जिन्दगी में इस्तेमाल करें। अगर हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भाषा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह कहना

कि किसी भा ा का इम्पीरियलिज्म है, यह सही नहीं है, यह गलत है। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हम रे आदरणीय रंगा जी कह रहे थे कि मैं तेलुगु भाषा मे बोलना च हता था लेकिन इजाजत नहीं मिली। मैं भी बोलना चाहता हूं। पहले दिन मैं यहां जब आया तो मैं तेलुगु मे बोला लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। यह कहा गया कि इसके अनुवाद का प्रबंध नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका प्रबंध हो। मैंने लिख कर भी दिया कि तेलुगु भाषा के अनुवाद का इंतजाम हो लेकिन आज तक नही हुआ। फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि जब तक अनुवाद का इंतजाम नहीं होगा मैं हिन्दी भाषा या और किसी भाषा में नहीं बोलूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। मै जरूर कहूंगा कि हिन्दुस्त न की जो भाषाएं है मैं उनमे बोलूंगा। हिन्दुस्तान की जो भाषाएं हैं उनमें विचार अपने रखूंगा। इसी तरह से हर माननीय सदस्य जो यहां पर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपनी भावनाओं को अपने विचारों को हिन्दुस्तान की जनता की भाषा में कहे। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हिन्दुस्तान की जनता के सामने उनकी भाषा में बोलते हैं उनकी भाषा मे कह कर वोट मांगते हैं। जब हम यहां आते हैं तो हम उनकी भाषा में नहीं बोलते। हम नोट लिखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहूंगा कि माननीय सदस्य भाषा के बारे में झगड़ा न करें और न ही झगड़े की जरूरत है। जिस भाषा मे वे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं करें। अगर किसी भाषा में नहीं कर सकते तो अपनी मातृ-भाषा में करें जिसके अनुवाद की व्यवस्था सदन के अन्दर की जानी चाहिए। जिस तरीके मे अगर मैं तेलुगु में बोलना चाहता हूं तो मुझे यह अवसर मिलना चाहिए कि मैं अपनी भाषा में बोलूं ताकि दूसरे सुन सकें कि तेलुगु भाषा किस किस्म की भाषा हो सकती है और मैं यह सुन सकूं कि तामिल किस किस्म की भाषा है। हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है इसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी बोली जाती है तो मैं यह देखूंगा कि मराठी भाषा किस तरह से तेलुगु से मिलती जुलती है, इसी तरह से तेलुगु से तामिल कैसे मिलती जुलती है, मलयालम कैसे हिन्दी से मिलती जुलती है। हर भाषा एक दूसरे से मिलती जरूर है हर भाषा में ऐसे शब्द होते है जो दूसरी भाषाओं में होते हैं, इसलिए हम हर भाषा को जानने की कोशिश करेंगे। किसी भाषा को सीखने से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं अंग्रेजी, रूसी, जापानी सीखना चाहूंगा, जर्मन और इटालियन भी सीखना चाहूंगा। भाषा सीखने में कोई एतराज नहीं है। हम सभी भाषाओं को सीख सकते है, जितनी भाषाएं सीखेंगे उतना ही फायदा है, सारी दुनिया में घूम सकेंगे। दुनिया के किसी हिस्से में जायेंगे तो वहां के लोगों की भाषा में बात कर सकेंगे, अपनी बात समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जायेंगे तो उनकी जुबान में यदि बोलेंगे तो वे खुश होंगे, उनकी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए किसी को किसी भाषा के बारे में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जहां तक हिन्दी भाषा का सवाल है, मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई पत्र हिन्दी में आता है तो उसका जवाब हिन्दी मे देने की कोशिश करता हूं, तेलुगु में आता है तो तेलुगु में देने की कोशिश करता हूं, अंग्रेजी में आता है तो अंग्रेजी में देने की कोशिश करता हूं, इसी तरीके से अगर मराठी में आता है, जो थोड़ी बहुत मैं जानता हूं उसमें भी लिखने की कोशिश करता हूं। परन्तु एक चीज मैं हिन्दी भाषा के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि यह बिल जो मेरे पास है इसको मैंने पढ़कर समझने की कोशिश की तो मुश्किल लगा मैं कहना यह

[श्री सत्यनारायण रेड्डी]

चाहता हूं कि हिन्दी को सरल बनाना चाहिए ताकि यह सारे हिन्दुस्तान की भाषा बनी रहे, यह न हो कि इसको कठिन से कठिन बनाया जाय इससे लोग यह समझेंगे कि यह हमारी समझ में आने वाली भाषा नहीं है। जब हम जय प्रकाश नारायणकी तकरीर सुनते हैं, किताब पढ़ते है तो अच्छी तरह से समझ में आती हैं मगर इसको जब मैं पढ़कर समझने की कोशिश करता हूं तो यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसका क्या मतलब है, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि इसको हर आदमी हिन्दुस्तान का समझे, पढ़े। अगर इसको कठिन से कठिन बनाया जायेगा या कोशिश करेंगे तो यह भाषा जनता से दूर हो जायगी, जनता के करीब नहीं जायेगी इसलिए भाषा को सरल बनाना चाहिए। हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है और हमें कबूल है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा बनाये रखने की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए इसको सरल बनाना चाहिए।

मैं एक और चीज यहां मंत्री महोदय से कहूंगा कि यदि कोई कानून हो, कोई चीज हो तो हर भाषा में उसका अनुवाद होना ही चाहिए। हिन्दुस्तान की जितनी भाषाएं हैं उन सबमें अनुवाद होना चाहिए जिससे हिन्दुस्तान के सभी लोग उसको समझें। उस स्थिति में क्या होता है, क्या कहते हैं कि ये सब चीजें हिन्दुस्तान की जनता जाने और वह तभी जान सकती है जब उनकी भाषा में अनुवाद होगा, वह अदालत हो या मदरसा हो या स्कूल हो या कोई चीज हो हर जगह वहां के लोगों की जुबान में उसका प्रबंध हो, अनुवाद हो तभी हिन्दुस्तान के लोग उस चीज को समझेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस जुबान के बारे में हम झगड़ा ना करते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा सरल बनायेंगे और ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान की जुबानों को इस्तेमाल करके किसी ढंग से, किसी तरीके से इस्तेमाल में लाकर उसको ज्यादा मकबूल करेंगे। हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का चाहे वे इस ओर के हों या उस ओर के, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बहस में भाग लिया और कुछ बहुत ही बढ़िया सुझाव पेश किये जिससे हम अपनी भारतीय भाषाओं को, राष्ट्रीय भाषा को और भी अधिक जनता के पास ले जाने में कामयाब होंगे। महोदय, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है इसलिये कि सभी माननीय सदस्यों ने बिना अपवाद के इस विधेयक का स्वागत किया है। इस विधेयक में जो उपबन्ध दिये गये हैं, उसका स्वागत किया है।

महोदय, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिये था। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा जो काम पहले हो जाना चाहिये था और जो अब हो रहा है उसमें अब कोई और विलम्ब न हो, देर न हो इसकी चिन्ता हमें है। माननीय सदस्यों को है और मैं उससे सहमत हूं। जो सुझाव दिये गये है महोदय, उसमें से किसी भी सुझाव से, किसी भी मशविरे से, किसी भी राय से मेरी असहमति नहीं है। सभी सुझावों से, जो भी माननीय सदस्यों द्वारा यहां आये हैं सभी से मेरी सहमति है। मसलन, जो माननीय सदस्य ने कहा भाषा का क्या रूप होना चाहिये, भाषा सरल होनी चाहिये, भाषा सुबोध होनी चाहिये, भाषा जनभाषा बननी चाहिये, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं हो सकता है। यह सुझाव आया कि हिन्दी ही नहीं, सभी भाषाओं में संविधान का प्राधिकृत अनुवाद होना चाहिये, इसका उपबन्ध इस विधेयक में है। इसकी जो तीसरी धारा है, उसमें इसका उपबन्ध है। जो माननीय सदस्य प्रो० रंगा साहब ने सुझाव दिया है ऐसा तो कोई संशोधन

आया नहीं है । उन्होंने जो सुझाव दिया है कि आप अपने ही हाथ इस तरह का कोई संशोधन लाइये, तो महोदय मैं उनकी इस आशंका को, इस भय को.....

PROF. N. G. RANGA: The House will give you permission.

श्री घनिक लाल मंडल : ...दूर करना चाहता हूं । हम लोगों की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है । जो भारत की अन्य भाषाएं हैं, वे सभी राष्ट्र भाषाएं हैं आठवीं सूची में जिन भाषाओं का भी उल्लेख है उन सभी को हम बराबर का दर्जा देते हैं, कोई कमोबेश दर्जा नहीं देते है और सभी को राष्ट्र भाषा मानते है । यह दूसरी बात है कि हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है संविधान में । लेकिन इस उपबन्ध के बावजूद भी हम मानते है कि हिन्दुस्तानी का जो मुकाम है, चाहे संविधान में दिया हुआ है वह मुकाम भी तभी मिल पायगा जबकि सभी भारतीय भाषाएं तरक्की करेंगी और अपना-अपना स्थान लेंगी । जब तक सभी भाषाएं अपने-अपने मुकाम पर नहीं पहुंचती है, तब तक हिन्दी भी अपना स्थान नहीं ले पायेगी । अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पायेगी । यह हमारा विश्वास है । पक्का विश्वास है । इसलिये यह आशंका करना कि केवल हम हिन्दी का ही प्राधिकृत अनुवाद निकालेंगे और दूसरी भाषाओं का नहीं निकालेंगे, उसमें नई टाल-मटोल की नीति अपनायेंगे, ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये ।

मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी ओर से ऐसा नहीं किया जायगा, बल्कि इस काम को और आगे बढ़ाने के लिये पिछले दिनों हमने राज्य भाषाओं का सम्मेलन किया था, विगत वर्ष 1977 में हमने राज्य भाषाओं का सम्मेलन किया था, राजभाषा का ही नहीं । इस देश में जितनी भी भाषाएं चल रही हैं, जिन राज्यों में जो भी भाषाएं स्वीकृत हैं, उन सबों का एक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में बैठ कर हम ने सभी भाषाओं के विकास के लिये और वह अपने मकाम पर पहुंचें, वह अपना उचित स्थान लें इस के लिये हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया और आगे भी यह सिलसिला हम जारी रखने वाले हैं । उस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किये वे सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए और इस लिये हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मन मे कोई आशंका नहीं है । इस लिये मै अपने माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम हमारी ओर से नहीं होने वाला है जो कि उन की भावना को ठेस पहुंचाने वाला हो या उन के इस लक्ष्य में बाधक हो । वह काम साधक ही होगा । मैं माननीय सदस्य जो तमिलनाडु के हैं या आंध्र प्रदेश के हैं उन की भावनाओं को जानता हूं और हमारी भी अपनी जो भावनायें है, जैसा कि मैंने बतलाया कि हमारी यह भावना है, हमारा यही विश्वास है कि जब तक सभी भारतीय भाषाओं का विकास नहीं होगा, जब तक सभी भारतीय भाषायें अपना उचित स्थान नहीं लेंगी, अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेंगी तब तक हिन्दी, हिन्दुस्तानी भी अपना मुकाम नहीं ले पायेगी । सभी भाषायें आपस में मिल कर सहयोग कर के ही अंग्रेजी का स्थान ले पायेंगी, नहीं तो वह अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती । इस लिये हम कोई ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं यह माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से बतला देना चाहता हूं । इस में हमारे मन में कोई आशंका नहीं है ।

महोदय, जो यह बात कही गयी है कि 73 में जो कानून बना प्राधिकृत अधिनियम कानून, उसी में संशोधन कर के यह काम भी कर लिया जाता तो ठीक रहता । इस संबंध में मेरी यह गुजारिश है कि जो संविधान का दर्जा है वह दूसरे कानूनों से ऊंचा है और इस लिये जब हम संविधान के उपबंधों के संबंध में कुछ करना चाहते हैं तो उस के लिये

[श्री धनिक लाल मंडल]

अच्छा होगा कि अलग से कुछ प्रावधान किया जाय और ऐसी ही राय विधि विभाग की थी। इस लिये यह विधेयक अलग से लाया गया है। इसमें और कोई बात नहीं है। [illegible]

और भी जो बातें उठायी गयीं कि भाषा जोड़ने वाली होनी चाहिए, तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, भाषा बोधगम्य होनी चाहिए, दुरूह नहीं होनी चाहिए, भाषा आम फहम होनी चाहिए, भाषा कुछ लोगों की नहीं होनी चाहिए कि जो एलाइड कहलाते हैं, उनकी नहीं होनी चाहिए, इन सारी बातों से मेरी सहमति है। मैं इन से इत्तफाक रखता हूं और इस लिये हम जो कुछ आगे करने वाले हैं वह इसी रोशनी में करने वाले हैं। अभी तक जो काम हुआ, दुर्भाग्य से वह इस आधार पर नहीं हुआ। अभी तक अनुवाद पर काम होता रहा और अनुवाद की भाषा आप जानते हैं, दुरूह होती है, क्लिष्ट होती है। वह बोधगम्य नहीं होती। लेकिन यह हमारी लाचारी है, मजबूरी है क्योंकि हम को ट्रांस्लेशन से ही काम लेना होता है। इस लिये यह हमारी कठिनाई है। जो यह सुझाव रखे गये कि ट्रांस्लेशन में भी जो शब्द आ गये हैं जो हिन्दी की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार नहीं है उनको बदल कर क्लिष्ट शब्दों को निकाल कर दूसरे शब्दों को लिया जा सकता है। अभी तक कई स्थानों पर क्लिष्ट शब्दों को रखा गया है, मसलन कहा गया कि स्टेशन, सिगनल या रेल के नये शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन को ही रखा जा सकता था। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन के संबंध में हम लोगों को अनुदेश दिये हैं। हम लोग जब से आये हैं, हम लोगों ने इस एक साल में इस पर बहुत ध्यान दिया है और जो भावनायें माननीय सदस्यों की हैं उनके अनुरूप ही आदेश दिये गये हैं और हम आगे इस बात की पूरी चेष्टा रखेंगे और पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि भाषा किसी एक स्थान की भाषा न हो, बल्कि वह पूरे देश की भाषा हो और वह भाषा किसी अनुवाद की भाषा न हो, वह भाषा मौलिक भाषा हो। उस में सभी भाषाओं के शब्द आयें। तो यह सारे सुझाव जो आये है उन के अनुरूप आदेश दिये जा रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आगे भी इस संबंध में ध्यान रखेंगे। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनके अनुरूप हम और भी ध्यान देंगे।

महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा कि यह इम्पीरियलिस्ट भाषा है और लादी जा रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी इंपीरियलिस्ट भाषा नहीं है बल्कि दूसरी बात जो कही जाती है वह अधिक सही है कि यह गंवारू भाषा है, गांव की भाषा है। कुछ लोग है जो हिन्दी का अपमान करने के लिए जहां तहां से जो शब्द मिल जाते हैं, वह वहां से वे शब्द ले आते हैं। कभी कभी कहते हैं कि यह साम्राज्यवादी भाषा है। हिन्दी कभी साम्राज्यवादी भाषा बन गई हो या लादी गई हो यह हमको पता नहीं। लेकिन एक बात वह लोग कहते हैं कि यह हलवाहों की, चरवाहों की भाषा है, गांव वालों की भाषा है। उनकी इस बात में दम है। यही इसकी खूबी भी है। यह जो हलवाहों की, चरवाहों की, गंवारों की भाषा है, जंगलों की भाषा है उसमें थोड़ा दम जरूर है। यह इसकी खूबी भी है। इसीलिए यह आम लोगों की भाषा है। इसमें हमको लज्जा का अनुभव नहीं होता। लेकिन एक बात है कि कोई भी भाषा तभी विकसित होती है जब कि उसको काम करने का मौका आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कह दिया जाए कि भाषा पहले विकसित हो ले फिर स्थान ले। ऐसा कभी हुआ नहीं है। यह तर्क वही लोग देते हैं जो कभी भी इस भाषा को स्थान नहीं देना चाहते। लेकिन भाषण देकर, वोट

लेना चाहते हैं। लोगों को बरगलाकर व ऐसी बात कह सकते हैं। जो ईमानदारी की बात है वह यही है कि भाषा जब व्यवहार में आता है, कामकाज में आती है तभी वह भाषा मंजती है, घिसती है, तभी वह ऐक्जेक्ट भी बनता है, वह स्पष्ट भी बनती है। ऐसे ही भाषा नहीं बना करती जिसे काम करने का अवसर न मिला हो। दुनिया इस बात का प्रमाण है। जब कोई नया इतिहास बनायेंगे तब जाकर देखेंगे लेकिन आज तक दुनिया में जो विकास हुआ है, स्वयं अंग्रेजी का जो विकास हुआ है वह ऐसे ही हुआ है। इसलिए यदि सभी भारतीय भाषाओं को, मैं केवल हिन्दी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय सभाषाओं की बात कर रहा हूं, सभी भारतीय भाषाओं का विकास करना है तो उनमें भी यही गुण होने चाहिए कि सभी प्रकार के शब्द उनमें आ जायें। उनके स्पष्ट, सुस्पष्ट अर्थ हों, एक अर्थ हों यह बात कही जाती है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब भाषाओं का व्यवहार हो, कामकाज में वह भाषायें आयें। नहीं तो वही बात होगी जिसके बारे में हमको डर है कि भाषा दुरूह होगी, भाषा क्लिष्ट होगी, भाषा नकली होगी, बनावटी होगी। भाषा जीवन्त नहीं हो सकती है, प्राणवान नहीं हो सकती है, प्रवाहमयी नहीं हो सकती है जब तक कि उसमें ये गुण न हों। उसमें ये गुण तभी आते हैं जब कि भाषा व्यवहार में आती है, कामकाज में आती है। तभी जाकर ये सभी गुण उसमें आते हैं। नहीं तो ट्रांसलेशन की भाषा होगी जिसके बारे में सही कहा गया है कि वह दुरूह हो गई है, क्लिष्ट हो गई है, यह भाषा बोधगम्य नहीं है, यह भाषा नकली है, यह भाषा गढ़ी हुई है। ये सारी चीजें कही जा सकती हैं। इसलिए भाषा का प्रयोग करना ही होगा।

श्रीमन्, जैसा मैंने शुरू में कहा जितना भी उन्माद दिखलाया जाए, शोर-शराबा, जोश-खरोश दिखाया जाए, लेकिन बात वही है कि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य तो डंडे से नहीं भाषा से चलता है। यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, यदि हम अपने देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं तो उसका जरिया भाषा ही हो सकती है। डंडे से हम चलाना चाहें मनुष्य को तो वह नहीं चलेगा। यह प्रेरणा से ही चल सकता है और वह प्रेरणा भाषा ही दे सकती है। कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तरफ तो देश का विकास करना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं और उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम देश की भाषा में यह नहीं करना चाहते हैं। मैं हिन्दी की बात नहीं कर रहा हूं देश की भाषाओं की बात कर रहा हूं। देश की भाषाओं में हम काम नहीं कर रहे हैं उसका फल आज आप देख रहे हैं, देश का जो विकास हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। देश के विकास के नाम पर कुछ लोगों का विकास हो गया है। जब तक जिसकी जो भाषा है उनको भाषा में, उनकी बोली में उनको प्रेरित नहीं करेंगे, हम उनको नहीं हांकेंगे तब तक हम देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्व पूर्ण प्रश्न है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को विकसित करके उनको अपने मुकाम पर पहुंचाना हमारा काम है। देश के विकास के काम में हमारा विश्वास है और इसमें किसी भाषा को किसी पर थोपने का कोई सवाल नहीं है। यहां पर बार बार यह आश्वासन दिया गया है और मैं पुनः उस आश्वासन को दोहराता हूं कि किसी एक भाषा को किसी दूसरी भाषा पर थोपने का सवाल नहीं है। हम तो महज दूसरी बात भी कहते हैं। हम तमिलनाडु वाले लोगों से कहते हैं कि तमिल में अपना कामकाज करो, हम आंध्रा वालों से कहते हैं कि अपना काम तेलुगु में करो, हम कर्नाटक वालों से कहते हैं कि

[श्री धनिक लाल मंडल]

अपना काम कन्नड़ में करो, केरल वालों से कहते हैं कि अपना काम मलयालम मे करो, अपनी अपनी भाषा मे काम करो। इसी उद्देश्य से हमने राजभाषा सम्मेलन किया था, उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। जहां जिसका स्थान है, मुकाम है उनको वहीं पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इसी दृष्टि से यह सम्मेलन हुआ था। इसी उद्देश्य से हम यह विधेयक लाये हैं। हम चाहते हैं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं जिनका अष्टम सूची मे अनुबंध है, उल्लेख है उसमें संविधान का अनुवाद उपलब्ध हो जिससे न्यायालय में भी उसका उपयोग हो सके और न्याय सस्ता और सुलभ बने। यह हमारा काम है। और भी दूसरे जो काम हैं वे भी करने हैं।

अभी नत्थी सिंह जी ने पूछा कि आप कितने दिनों में यह काम करने वाले हैं। क्योंकि 30 वर्षों से हम कहते आए हैं लेकिन कर नहीं पाये हैं। उन्होंने कुछ साधुवाद भी दिया हम लोगों को। हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग से भारतीय भाषाओं को परीक्षा माध्यम बनाया इसके लिये उन्होंने हमें साधुवाद दिया। उन्होंने कहा आपने एक अच्छे काम की शुरूआत की है। और भी जो दूसरे काम किये हैं उनके लिये भी उन्होंने बधाई दी लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि यह काम आप कितने दिनों मे करने वाले हैं। मैं इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि इतने समय में यह काम होने वाला है। क्योंकि यह तो सभी के सहयोग पर निर्भर करता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयास है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पाई जाए, भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रशासनिक काम हो और भारतीय भाषाओं के माध्यम से लोगों को न्याय मिले, यह हमारी कोशिश हो रही है और इस दिशा में जो भी हम को आवश्यक कदम उठाने पड़ रहे हैं उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं। यह भी विधेयक उसी दिशा मे एक प्रयास है। जैसा कि सदन के चारों ओर से इसका स्वागत हुआ है मैं इसको समझता हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लगा इसलिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं और यह चाहता हूं कि आप इसको पारित कर दें और कोई आशंका, कुशंका मन में न रखें। हम लोग हिन्दी के ही नहीं भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं और उसके विकास के अग्रगामी हैं।

SHRI B. N. BANERJEE: Sir, the hon. Minister will see that there are 15 languages in the Eighth Schedule. It is not necessary to read out the names of all the languages. The hon. Minister has also stated that the work will be done by the Translation Wing of the Ministry of Law, Legislative Department. Has the hon. Minister made sure that this work will be done in the Translation Wing of the Ministry of Law in all these 15 languages? If so, what is the information?

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मुझे इस बारे में विभाग से जो सूचना मिली है उसके अनुसार तैयार हो रही है।

SHRI B. N. BANERJEE: By whom? Who are doing it? Are there translators in all these languages in the Ministry of Law?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: It will be translated authoritatively in all the languages included in the Eighth Schedule. That arrangement has been made by this Department.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAMBHAI OZA): The question is:

"That the Bill to provide for authorised translations of the Constitution, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAMBHAI OZA): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE PRIZE CHITS AND MONEY CIRCULATION SCHEMES (BANNING) BILL, 1978

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): Sir, I beg to move:

"That the Bill to ban the promotion or conduct of prize chits and money circulation schemes and for matters connected therewith or incidential thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill which I want to move deals with the banning of the promotion or conduct of Prize Chits or Money Circulation Schemes and matters connected therewith. In the context of the decisions taken by Government on the recommendations of the Banking Commission (1972) for restructuring of existing scheme of control over the activities of the non-financial intermediaries, the Reserve Bank constituted in June, 1974 a Study Group under the Chairmanship of Shri James S. Raj with a view to examining the matter in all its aspects. This Study Group submitted its report to the Reserve Bank in July, 1975. The Study Group concluded that prize chits or benefit schemes benefit primarily the promoters and do not serve any social purpose According to the Study Group, they are prejudicial to the public interest and also adversely affect the efficacy of the fiscal and monetary policy of the country. There has also been a public demand for the banning of such schemes; this stems largely from the malpractices indulged in by the promoters and also the possible exploitation of such schemes by unscrupulous elements to their own advantage. Accordingly, the Study Group has recommeded that the conduct of prize chits, or benefit schemes by whatever name called should be totally banned in the larger interest or the public and that suitable legislative measures should be taken for the purpose.

I may mention that miscellaneous non-banking companies are of two types, namely (a) those conducting prize chits, benefit/savings schemes, lucky draws, etc.; and (b) those conducting conventional or customary chit funds. The present Bill deals with the banning of the promotion and conduct of prize chits, benefit schemes. A separate Bill for regulating activities of the conventional chit funds is proposed to be introduced later.

It would be useful to mention here the difference between these two kinds of chits. Prize Chits would cover any kind of arrangement under which moneys are collected by way of subscriptions, contribution, etc., and prizes, gifts, etc. are awarded. The *modus operandi* is that the foreman or the promoter who ostensibly charges no commission, collects subscription in one lumpsum or by monthly instalments spread over a specified period from the subscribers to the scheme. Periodically, the numbers allotted to members holding the tickets or units are put to a draw and the member holding the lucky ticket gets the prize either in cash or in the form of an article of utility.